नई दिल्ली में सस्टनेबल डेवलपमेंट सम्मिट के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बेस्ट लीडर शिप का अवॉर्ड देते हुए।

जलवायु परिवर्तन पर न

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को 11वें दिल्ली सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद किया दावा

नई दिल्ली। विकासशील देशों से भी उत्सर्जन कटौती संबंधी बाध्यकारी शर्तें स्वीकार करने की पर्यावरण एवं वनमंत्री जयराम रमेश की अपील से उलट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को साफ कहा कि फिलहाल इन देशों को उत्सर्जन कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य मानने की कोई जरूरत नहीं है और जलवायु परिवर्तन पर भारत के इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

डॉ. सिंह ने ऊर्जा स्रोत संस्थान (टेदी) के तत्वावधान में बृहस्पतिवार सुबह यहां स्थायी विकास पर 11वें दिल्ली सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं और जो उत्सर्जन कटौती करने में सबसे ज्यादा सक्षम भी हैं; कटौती का भार भी उन्हें ही उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए विकासशील देश बहुत कम जिम्मेदार हैं, दूसरे निरंतर विकास की उनकी बृहत्तर जरूरतों के मद्देनजर इन देशों को स्थायी विकास के लक्ष्य हासिल करने में मदद की जानी चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए 'समन्वित वैश्विक कार्रवाई' का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे विकासशील देश में स्थानीय या राष्ट्रीय दुनियाभर में अपेक्षित उत्सर्जन-कटौती के संदर्भ में बहुत कारगर नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया भर में ग्रीनहाउस जैसों के सकल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा केवल 4 प्रतिशत है और अगर भारत यह उत्सर्जन पूरी तरह रोक भी ले तो जलवायु परिवर्तन की मौजूदा स्थिति में शायद ही कोई फर्क पड़े। ज्ञातव्य है कि हाल में कानकुन में जलवायु पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रमेश ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि उत्सर्जन कटौती की कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं विकासशील देशों को भी स्वीकार कर लेनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कानकुन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुख्य मसलों तथा अन्य संबंधित मुद्दों का समाधान तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे कुछ परिणाम तो मिले ही हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि मैं सम्मेलन में उल्लेखनीय नेतृत्व के लिए और लक्ष्य की ओर थोड़ी प्रगति के लिए मेक्सिको को बधाई देता हूं। इससे स्पष्ट है कि सामूहिक संकल्पशक्ति से अब भी एक सार्थक अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाना संभव है, भले ही यह पहले से मुश्किल हो गया हो। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप समझौते के तहत प्रौद्योगिकी प्राकलन केन्द्रों का संजाल बनाने के करार का स्वागत किया।■

अरूणाच

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री
अंग रहा है और रहेगा त
बदल जाएगी। आल अ
प्रधानमंत्री ने आप्सू प्रति
से कहा कि अरूणाचल

चीन द्वारा अरूणाचल
सरकार इस समस्या के
अरूणाचल को अलग
तरह उसे भी पहुंचने चाहि
जिक्र करते हुए कहा कि
सरकारें विकास की गति
प्रधानमंत्री के संज्ञान मे
अरूणचल सीमा विवाद